

## लूट, घोटाला, गड़बड़झाला!

### एक व्यवस्था, अनेक सवाल और जनता का हिसाब

भारत केवल चुनावों से लोकतांत्रिक नहीं बनता; लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब जनता के पैसे, अधिकार और विश्वास—तीनों की रक्षा हो। लेकिन आज “लूट, घोटाला और गड़बड़झाला” केवल राजनीतिक शब्दावली नहीं रह गए हैं, बल्कि आम नागरिक के मन में उठते उन सवालों का प्रतीक बन चुके हैं, जिनका जवाब व्यवस्था को देना होगा।

लूट केवल जेब से पैसा निकालना नहीं है। जब गरीब को उसका हक नहीं मिलता, युवा को योग्यता के बावजूद अवसर नहीं मिलता, किसान को अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिलता और आम नागरिक को अपने ही काम के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं—कृतो यह भी व्यवस्था के स्तर पर अधिकारों की लूट है।

घोटाला केवल धन का नहीं होता—विश्वास का भी होता है। जनता चुनाव में भरोसा करती है कि उसके प्रतिनिधि उसके हित में काम करेंगे। जब सत्ता जनसेवा के बजाय स्वार्थ, पक्षपात, भाई—भतीजावाद या भ्रष्टाचार का माध्यम बनती है, तब लोकतंत्र की आत्मा घायल होती है।

सबसे खतरनाक है गड़बड़झाला—जहां नियम हैं लेकिन पालन कमजोर है, संस्थाएं हैं लेकिन जवाबदेही कमजोर है, योजनाएं हैं लेकिन लाभार्थी तक लाभ नहीं पहुंचता और शिकायतें हैं लेकिन समाधान वर्षों तक लंबित रहता है।

राजनीति का उद्देश्य सत्ता हासिल करना नहीं, जनता की सेवा करना होना चाहिए। चुनाव के समय जनता को “मालिक” और चुनाव के बाद “याचक” बना देना लोकतांत्रिक भावना के विपरीत है। सत्ता जनता की अमानत है और हर सार्वजनिक पद एक जिम्मेदारी है—विशेषाधिकार नहीं।

लेकिन जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है। समाज को भी आत्ममंथन करना होगा। रिश्ते देकर काम करवाना, भ्रष्ट व्यक्ति को उसकी संपत्ति के कारण सम्मान देना और गलत व्यवस्था को “चलता है” कहकर स्वीकार कर लेना—कृते सब भ्रष्टाचार को सामाजिक स्वीकृति देते हैं।

आज आवश्यकता किसी अराजक आंदोलन की नहीं, बल्कि जागरूक नागरिक चेतना, पारदर्शिता, कानून के शासन और कठोर जवाबदेही की है। युवा वर्ग को केवल दर्शक नहीं, लोकतंत्र का सक्रिय प्रहरी बनना होगा। सवाल पूछना लोकतंत्र विरोधी नहीं—लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण ताकत है।

All India Human Rights Association (AIHRA) का स्पष्ट संदेश है कि मानवाधिकार केवल पुस्तकों या भाषणों का विषय नहीं। सम्मानपूर्वक जीवन, समान अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा और गरिमा—मानवीय अधिकारों की बुनियाद हैं। किसी भी व्यवस्था की वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि उसका सबसे कमजोर नागरिक कितना सुरक्षित, सम्मानित और न्यायसंगत जीवन जी रहा है।

अब समय है कि जनता केवल नारों से नहीं, जवाबदेही से सवाल पूछे। पैसा कहां गया? योजना का लाभ किसे मिला? जिम्मेदार कौन है? और जवाब कब मिलेगा?

लोकतंत्र में जनता की आवाज दबाई नहीं जानी चाहिए—सुनी जानी चाहिए।

क्योंकि—लूट बंद होनी चाहिए। घोटाले पर जवाबदेही होनी चाहिए। गड़बड़झाले की जगह पारदर्शिता होनी चाहिए। और जनता को उसके अधिकारों का पूरा सम्मान मिलना चाहिए।

न डर, न अंधसमर्थन—सिर्फ संविधान, मानवाधिकार और जवाबदेही।

जय मानवता! जय मानवाधिकार! जय हिंद!

## LOOT, SCAM & SYSTEMIC CHAOS!

### One System, Many Questions—and the People Demand Answers

Dr. M. U. Dua | Global Leader – Human Rights | AIHRA

India does not become democratic merely because elections are held. Democracy becomes meaningful when public money, citizens' rights and public trust are protected. Today, “loot, scam and systemic chaos” have become more than political expressions—they represent the growing questions of ordinary citizens that the system must answer.

Loot is not merely the stealing of money from someone's pocket. When a poor person is denied what is rightfully due to them, when a deserving young person loses an opportunity despite merit, when farmers struggle to receive fair returns for their hard work, or when ordinary citizens are forced to run from office to office for basic services—rights are being denied and public trust is being looted.

A scam is not always about money. It can also be a scam of public trust. Citizens vote with the expectation that their representatives will work in the public interest. When power becomes an instrument of personal interest, favoritism, nepotism or corruption, the very spirit of democracy is weakened.

The most dangerous situation is systemic chaos—where rules exist but enforcement is weak, institutions exist but accountability is inadequate, schemes are announced but benefits fail to reach the intended people, and complaints remain unresolved for years.

Politics must mean public service, not merely the pursuit of power. Citizens cannot be treated as “masters” during

elections and reduced to petitioners after elections. Political power is a public trust, and every public office is a responsibility—not a personal privilege.

But responsibility does not rest with governments alone. Society must also look within. Paying bribes to get work done, celebrating wealth without questioning its source, and accepting corruption by saying “this is how things work” gives corruption social legitimacy.

What India needs is not anarchy or violence, but informed citizens, transparency, rule of law and genuine accountability. Young people must not remain spectators. They must become active guardians of democracy. Asking questions is not anti-national or anti-democratic—it is one of democracy's greatest strengths.

The All India Human Rights Association (AIHRA) firmly believes that human rights cannot remain limited to books, conferences or speeches. The right to live with dignity, equal opportunity, education, healthcare, justice and security forms the foundation of a humane society. The true measure of any system is not how powerful its privileged citizens are, but how safely and respectfully its weakest citizens can live.

The time has come for citizens to demand not merely promises, but accountability. Where did the public money go? Who benefited from the scheme? Who is responsible? And when will the people receive answers?

In a democracy, the voice of the people must not be suppressed—it must be heard.

Because—Loot must end. Scams must face accountability. Systemic chaos must give way to transparency. And citizens must receive the full respect of their human rights.

No fear. No blind support. Only Constitution, Human Rights and Accountability.

Jai Humanity! Jai Human Rights! Jai Hind!

